

न्यूज़ दुड़े

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सभी योजनाओं हेतु कार्य योजना 2020–21 जारी की गई

○ इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारों और भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य तथा प्रयोजन निर्धारित करना है।

योजना	योजना और प्रस्तावित कार्यों के बारे में
अनुसूचित जातियों (SCs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए निःशुल्क कोर्चिंग	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित SCs और OBCs छात्रों को गुणवत्ता युक्त कोर्चिंग कक्षाएं उपलब्ध करवाना है। <ul style="list-style-type: none"> ▷ कार्यान्वयन संबंधी नए तरीके के अंतर्गत पात्र SCs और OBCs छात्र, अपनी पसंद के संस्थान में कोर्चिंग हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
SCs के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसके तहत, अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षण (ट्यूशन) शुल्क, निवास संबंधी व्यय आदि को पूर्ण करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। <ul style="list-style-type: none"> ▷ इसके तहत सीटों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 4200 सीट प्रति वर्ष कर दी गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) / राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) / शीर्ष नेशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग वाले संस्थानों जैसी शीर्ष संस्थाओं को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस योजना में कुल 500 या 500 से अधिक की जनसंख्या और 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति (SC) की आबादी वाले गाँवों का समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आदर्श गाँवों में परिवर्तित किया जाएगा। <ul style="list-style-type: none"> ▷ इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों की बहुलता वाले 3584 गाँवों को शामिल किया गया है। इससे ऐसे गाँवों की कुल संख्या 13199 हो गई है।
भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों / स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों आदि के सहायता से भिखारियों की पहचान, पुनर्वास, रोजगार परामर्श, कौशल विकास आदि को समाविष्ट करने वाली एक व्यापक योजना है। <ul style="list-style-type: none"> ▷ मंत्रालय द्वारा व्यापक पुनर्वास के लिए एक परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को मुख्यतः 10 शहरों में प्रायोगिक आधार पर संचालित किया जाएगा।
स्वच्छता उद्यमी योजना	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस योजना को यंत्रीकृत सफाई को बढ़ावा देने और हाथ से मैला उठाने एवं इससे संबंधित जोखिमपूर्ण घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation) द्वारा प्रारंभ किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ▷ यह संगठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के अधीन है।
वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास योजना) (VISVAS Yojana)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस योजना के अंतर्गत SCs और OBCs के स्वयं सहायता समूह तथा कोई भी व्यक्ति बैंक ऋणों पर 5 प्रतिशत व्याज अनुदान प्राप्त कर सकते।
मादक द्रव्यों की मांग घटाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (वर्ष 2018–2023) (National Action Plan on Drug Demand Reduction) (2018-2023)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस योजना का उद्देश्य मादक द्रव्यों से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को शिक्षा, व्यसन मुक्ति (de-addiction) और उनके पुनर्वास सहित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के दुष्परिणामों को कम करना है। <ul style="list-style-type: none"> ▷ नशा मुक्त भारत अभियान को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से सर्वाधिक प्रभावित 272 जिलों में प्रारंभ किया गया है। ▷ यह अभियान 15 अगस्त, 2020 को आरंभ किया गया है और यह 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा।
अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	<ul style="list-style-type: none"> ○ पोस्ट मैट्रिक्युलेशन या पोस्ट-सेकेंडरी स्तर पर अध्ययनरत SC/OBC छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस कार्य योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की शीर्ष चार आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है, अर्थात्— वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानवीय अंतर्क्रिया / गरिमामय जीवन। <ul style="list-style-type: none"> ▷ इस वर्ष प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक वरिष्ठ नागरिक गृह (Senior Citizen Home) स्थापित किया जाएगा। ▷ इसी वर्ष वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी, जो वृद्धजनों की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्र, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और गैर-सरकारी संगठन को एक साझा मंच प्रदान करेगी। ▷ वरिष्ठ नागरिकों के डे-केयर सेंटर के लिए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं।

भारत, फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रथम त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई

- तीनों पक्षों ने वार्षिक आधार पर वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता का उद्देश्य इन देशों के मध्य साझा सुदृढ़ त्रिपक्षीय संबंधों की स्थापना द्वारा भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में सहयोगपूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- क्वाड्रिलेटरल (Quadrilateral) (भारत-स्युंक राज्य अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया) समूह के अतिरिक्त, भारत अग्रलिखित त्रिपक्षीय समूहों का भी एक भागीदार देश रहा है यथा: भारत-अमेरिका-जापान ;भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया; भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया तथा रूस-भारत-चीन।
- इस वार्ता की रूपरेखा विचार-मंच (थिंक टैक) विशेषज्ञों द्वारा निर्मित की गई थी, जिसमें इस क्षेत्र में ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 कूटनीति (Track 1.5 diplomacy) का प्राप्तवाय स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ था।
 - ट्रैक 1 कूटनीति— इस बैठक का आयोजन आधिकारिक स्तर पर किया जाता है। ट्रैक 2. इस वार्ता में अनौपचारिक प्रतिनिधि भाग लेते हैं न कि सरकारें। ट्रैक 1.5. इसके तहत अधिकारी अनौपचारिक रूप से भाग लेते हैं तथा गैर-अधिकारी अभिकर्ताओं के साथ मिलकर किसी राजनयिक वार्ता हेतु एक साथ कार्य करते हैं।
 - वार्ता में चर्चित रहे प्रमुख मुद्दे:
 - भारत-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और भू-रणनीतिक (geospatial) चुनौतियां एवं सहयोग: विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और इस संकट से निपटने हेतु घरेलू प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई।
 - मरीन ग्लोबल कॉमन्स (Marine Global Commons) पर सहयोग: ब्लू इकोनॉमी (नीतीय अर्थव्यवस्था), समुद्री जैव विविधता और समुद्री प्रदूषण आदि पर वार्ता की गई।
 - त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग, जिसमें आसियान (ASEAN), इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission) जैसे क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग शामिल है।
 - बहुपक्षीय संस्थानों की प्राथमिकताएं और चुनौतियां: उन्हें सुदृढ़ करने और उनमें सुधार करने के उपायों पर चर्चा की गई।
 - मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री प्रक्षेत्र में जागरूकता, पारस्परिक संभारण समर्थन (mutual logistics support) आदि क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

INSTANCES OF COLLABORATION IN INDO-PACIFIC

 Australia's \$50-b purchase of French submarines, which cemented a strategic partnership for security in the Indo-Pacific
 France's support of the International Solar Alliance on the margins of the Paris Agreement, creating the first international organisation headquartered in India
 Australia establishing a Space Agency last year, which led to partnerships with CNES, France's space agency, of which ISRO is a major global partner

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) के समेकन हेतु ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना (Village Poverty Reduction Plan: VPRP) के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सक्षम बनाया जा रहा है

- वर्ष 2018-19 से दीनदयाल अत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रक्रिया में भाग लेने और ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना (VPRP) तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है।
 - > यह निर्धन परिवारों, जो DAY-NRLM के तहत गठित SHGs के सदस्य हैं, को भागीदारी प्रक्रिया में अपनी मांगों को उठाने और अपनी अंतिम योजना (final plan) को विचार के लिए ग्राम पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।
 - DAY-NRLM का उद्देश्य 10-12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को SHGs में संगठित करके ग्रामीण निर्धनता को कम करना है।
- ग्राम पंचायतों को GPDP के निर्माण के लिए सौंधानिक रूप से अधिदेशित किया गया है, ताकि वे अपने गाँव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें।
- VPRP को SHGs और उनके संघों द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें GPDP के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होती है।
- VPRP के उद्देश्य:
 - > स्थानीय विकास के लिए समुदाय की एक व्यापक और समावेशी मांग योजना तैयार करना।
 - > मांग योजना के विकास के लिए SHG संघ (SHG federation) और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य एक इंटरफेस की सुविधा प्रदान करना।
 - > निर्धनता न्यूनीकरण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए समुदाय आधारित संगठनों और उनके नेतृत्व को सुदृढ़ करना।

विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund: WWF) द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट (LPR) 2020 जारी की गई है

- LPR को WWF द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में जारी किया जाता है। यह वैश्विक जैव विविधता और पृथ्वी के स्वास्थ्य से संबंधित परिवर्तनों का एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करती है।
 - > WWF, वन्यजीव और लुतप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक अग्रणी संगठन है।
- मुख्य निष्कर्ष
 - > वर्ष 1970 और वर्ष 2016 के मध्य वैश्विक वन्यजीव आबादी में 68% की गिरावट हुई है।
 - > पृथ्वी की 75% हिम युक्त भू-सतह में भी परिवर्तित हुई है।
 - > स्वच्छ जल में पाए जाने वाली प्रजातियों में लगभग तीन में से एक के विलुप्त होने का जोखिम बना हुआ है।
 - > 1700 ई. से अब तक वैश्विक स्तर पर लगभग 90% आर्द्धभूमियां लुप्त हो चुकी हैं।
 - > लैटिन अमेरिका में 94% की खतरनाक दर से वन्यजीवों की अधिसंख्यक आबादी की क्षति हुई है।
 - > विगत चार दशकों में भारत में हुए तीव्र शहरीकरण, कृषि विस्तार और प्रदूषण के कारण लगभग एक तिहाई प्राकृतिक आर्द्धभूमियों का हास हुआ है।
- जैव विविधता के समक्ष प्रमुख जोखिम: भूमि एवं समुद्र के उपयोग में परिवर्तन (जिसमें पर्यावास की क्षति एवं निम्नीकरण शामिल है) प्रजातियों का अतिरोहन; आक्रामक प्रजातियों का आगमन तथा रोग प्रसार; प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आदि जैसे कारक जैव विविधता संबंधी जोखिमों को बढ़ावा देते हैं।
- सुझाव: खाद्य उत्पादन और उपयोग के तरीकों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रयासों को तीव्र करने तथा प्रकृति को संरक्षित, सुरक्षित और पुनर्जागरित करने के लिए निवेश आवश्यक है। प्राकृतिक पूंजी को पुनर्प्राप्त करने हेतु आर्थिक प्रणालियों को भी परिवर्तित करना अपरिहार्य हो गया है।

अन्य सुर्खियाँ

भारत-अंगोला संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक (India-Angola First Joint Commission Meeting)	<ul style="list-style-type: none">○ इस बैठक में दोनों पक्षों द्वारा अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की गई और स्वास्थ्य, औषध, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलीकरण आदि क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने पर भी चर्चा की गई।○ आर्थिक विविधीकरण में अंगोला की सहायता करने तथा पेट्रोलियम और हीरा क्षेत्रों में अंगोला से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भारत ने अपनी विशेषज्ञता साझा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।> अंगोला, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है।
कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी (Convalescent plasma therapy)	<ul style="list-style-type: none">○ भारतीय आर्योजिनान अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Medical Research: ICMR) द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी, कोविड-19 रोगियों की सहायता करने में अप्रभावी रही है।○ प्लाज्मा थेरेपी के तहत कोविड-19 से उपचारित हो चुके व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा प्राप्त करके उसे उपचाराधीन रोगी में इंजेक्ट किया जाता है।○ रक्त प्लाज्मा रक्त का वह तरल घटक होता है, जिसमें रक्त कोशिकाएं प्रवाहित होती हैं। इसमें रोगप्रतिकारक (एंटीबॉडी) भी मौजूद होते हैं।
ANIC-ARISE चैलेंज (लघु और मध्यम उद्यमों हेतु एप्लाइड रिसर्च और इनोवेशन में अटल न्यू इंडिया चुनौतियों) नामक पहल का शुभारंभ किया गया (ANIC-ARISE (Atal New India Challenges in Applied Research and Innovation for medium and Small Enterprises) launched)	<ul style="list-style-type: none">○ यह अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्टअप एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करने हेतु अटल नवाचार मिशन द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है।> इसके अंतर्गत प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान और/या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।○ इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), चार मंत्रालयों अर्थात्-रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा।
भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय (Ancient Universities in India)	<ul style="list-style-type: none">○ तक्षशिला विश्वविद्यालय<ul style="list-style-type: none">> इसका निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है।> यहाँ बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मशास्त्रों की शिक्षा प्रदान की जाती थी।> तक्षशिला के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में चाणक्य, चरक, पाणिनि, जीवक, प्रसेनजित आदि शामिल हैं।○ नालंदा विश्वविद्यालय:<ul style="list-style-type: none">> इसे 5वीं शताब्दी ई. में कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है।> चीनी यात्री ह्वेन्सन्तांग और विद्वान् इत्सिंग के यात्रा वृत्तांतों में भी इसका उल्लेख मिलता है।> इससे संबद्ध प्रसिद्ध विद्वानों में नागार्जुन (माध्यमिक शून्यवाद) और आर्यभट्ट शामिल हैं।○ विक्रमशिला विश्वविद्यालय:<ul style="list-style-type: none">> इसे पाल वंश (बिहार का भागलपुर जिला) के शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था।> यह मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र रहा है। यहाँ वज्रयान संप्रदाय का उद्भव हुआ था और साथ ही, यहाँ तंत्रवाद संबंधी शिक्षाएँ भी प्रदान की जाती थीं।○ वल्लभी विश्वविद्यालय:<ul style="list-style-type: none">> इसे मैत्रक राजा भद्राक द्वारा सोरास्ट्र (गुजरात) में निर्मित करवाया गया था।> यह 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक अत्यधिक प्रचलित रहा था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

84680222022, 9019066066
www.visionias.in

